लोगों को पीड़ा पहुंचाए बगैर राजस्व के नए साधनों की तलाश

विद्यासागर
जनसत्ता संवाददाता

चंडीगढ़, 4 जुलाई। हरियाणा योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष मूलचंद जैन की सबसे बड़ी चिंता राज्य की आय के नए साधन जुटाना है लेकिन इस प्रक्रिया से वे लोगों को भी इसकी पीड़ा महसूस नहीं कराना चाहते।

योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद 72 वर्षीय श्री जैन ने जोरों से काम शुरू कर दिया है।

राज्य सचिवालय में जब जनसत्ता संवाददाता ने श्री जैन से आठवीं मंजिल पर उनके कार्यालय में भेंट की तो वे विभिन्न विभागों को लिखित रूप से निर्देश भेज रहे थे। इनमें यहां से शासन विभाग की जलमल बोर्ड के गठन संबंधी एक निर्देश भी था ताकि शहरों में पीने के पानी के बंदोबस्त व मल निकास के लिए विश्व बोर्ड से धन प्राप्त किया जा सके।

"मैं योजना बोर्ड का सक्रिय उपाध्यक्ष रहूंगा।" उनके इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं लगा क्योंकि व्यापक अनुभव प्राप्त गांधीवादी श्री जैन नैतिकता प्रधान राजनीति के जोरदार समर्थक हैं।

उनका कहना था, "हमें रोजगार के नए साधन भी जुटाने हैं ताकि बेरोजगारी की समस्या से मजबूती से निपटा जा सके।" उन्होंने कहा कि सरकार बेकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकी तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना होगा। उन्होंने रोजगार के साधन बढ़ाने के बारे में खादी आश्रम, पानीपत के प्रमुख सोम भाई से भी बातचीत की है।

श्री जैन का जन्म गोहाना (सोनीपत) के सिकंदरपुर माजरा गांव में निम्न मध्यम परिवार में हुआ था। गांव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई गोहाना में की। सनातन धर्म कालेज, लाहौर से स्नातक श्री जैन ने 1936 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से कानून की शिक्षा प्राप्त की। कानून की प्रारंभिक परीक्षा में वे विश्वविद्यालय में प्रथम रहे। 1937-38 में उन्होंने गोहाना से वकालत शुरू की और तभी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए।

श्री जैन को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके बारे में पूछने पर उनका जवाब था, "सरदार भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को मिली फांसी से मुझ में रोष की भावना ने जोर पकड़ा और मैं स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा।"

असौदा (रोहतक) में 1938 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे कार्यकर्ताओं पर जमींदारा लीग के समर्थकों ने घातक हथियारों से हमला किया। उस हमले में घायल हुए स्वयं सेवकों में श्री जैन भी थे। मार्च 1941 में उन्होंने वैयक्तिक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और उन्हें एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। 1942 में उन्होंने करनाल में 'भारत छोड़ो' आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें फिर एक साल की सजा देकर मुलतान (अब पाकिस्तान) जेल में बंद रखा गया।

कांग्रेस में जिम्मेदार पदों पर रहे श्री जैन का कारावास के दौरान सिंध के प्रमुख कांग्रेसी नेता चौथ राम गिडवानी, भीमसेन सच्चर, दीवान चमनलाल व अवतार नारायण से संपर्क हुआ।

गांधी टोपीधारी श्री जैन ने 1948-50 तक 'बलिदान' नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। इस दौरान उन्होंने करनाल जिला के पुराने मुजारों के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व भी किया जिन्हें पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के आने पर उन मुसलमान जमींदारों की जमीनों से उजाड़ा जा रहा था जो पाकिस्तान चले गए थे। आंदोलन सफल रहा और पंजाब सरकार को यह निर्देश जारी करना पड़ा कि उजाड़े गए मुजारों को उनकी पहले वाली जमीन दी जाए। श्री जैन 1952 में समालखा सीट से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए। मार्च 1956 में उन्हें प्रतापसिंह कैरों मंत्रिमंडल में आबकारी कराधान व लोकनिर्माण विभागों का मंत्री बनाया गया। वे 1957 में कैथल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गए। संसद सदस्य के नाते उनका संपर्क पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री व गोविंद बल्लभपंत से हुआ।

प्रगतिशील विचारों वाले श्री जैन सहकारी कृषि बोर्ड के भी सदस्य रह चुके हैं। यह तब की बात है जब सहकारी कृषि के मुद्दे पर पंडित नेहरू व चरणसिंह में खुल कर मतभेद सामने आए।

बाबू मूलचंद जैन

हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए किए गए आंदोलन में भी वे सक्रिय रहे। श्री जैन देवीलाल की अध्यक्षता में बनी सर्वदलीय हरियाणा संघर्ष समिति के महासचिव थे।

आपने कांग्रेस से नाता क्यों तोड़ा? श्री जैन ने जवाब दिया, "मैं 1967 में समालखा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुना गया लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने कांग्रेस के जिन उम्मीदवारों को हराने का प्रयास किया उनमें मैं भी था। भगवत दयाल की तानाशाही के कारण मुझे कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी।"

राव वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनी हरियाणा की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में श्री जैन वित्त मंत्री थे। जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन के दौरान बनी हरियाणा संघर्ष समिति की कार्यसमिति के सदस्य रहे श्री जैन आपातकाल के दौरान 19 मास जेल में रहे। 1977 में वे समालखा सीट से जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए। देवीलाल ने शुरू में तो नहीं लेकिन दिसंबर 1978 में उन्हें अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनाया। 1980 से मई 1982 तक वे विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। विपक्ष के नेता के नाते उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई में गहरी रुचि ली।

इस बार श्री जैन ने चुनाव तो नहीं लड़ा लेकिन वे लोकदल (ब) की चुनाव समिति व चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने वाली समिति के सदस्य थे। उनका कहना था, "मैं मंत्रियों व विधायकों को चुनाव घोषणा पत्र के मुद्दे पर याद करवाता रहूंगा।"

उन्होंने कहा कि, "मेरा काम वरिष्ठ अधिकारियों में यह विश्वास पैदा करना होगा कि नई सरकार जन हित के मामलों को प्राथमिकता देने वाली सरकार है।"

श्री जैन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि योजना की प्राथमिकता भूमिहीनों व गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा। हरियाणा में कृषि-उत्पादन भी बढ़ाना होगा क्योंकि राज्य की अब तक की समृद्धि कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति से संभव हो सकी थी।

श्री जैन ने राज्य की आय के अतिरिक्त साधन जुटाने की चर्चा करते हुए कहा, "देवीलाल मंत्रिमंडल में जब मैं वित्त मंत्री था, तब मैंने हरियाणा में उन कारखानों के उत्पादनों पर एक टैक्स लगाया था, जिन के मुख्यालय हरियाणा से बाहर दिल्ली व कहीं और हैं। श्री जैन ने बताया कि बाद में भजन लाल सरकार ने इस टैक्स को समाप्त कर दिया था। अब फिर श्री जैन ने संबंधित विभाग से इस बारे में पूछताछ की है।

सत्तारूढ़ दल के विधायकों की संपत्ति की जब बात चली तो जैन ने कहा कि लोकदल (ब) के विधायकों को अपनी-अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा, "पार्टी के स्तर पर इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

Downloaded from moolchandjain.org